बजट 2023-24

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला दूरदर्शी बजट

-श्री नरेंद्र सिंह तोमर

अमृतकाल का यह पहला बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है। बजट में किसानों के साथ ही गरीब व मध्यम वर्ग और महिलाओं से लेकर युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का समावेश किया गया है। इस बजट में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के कारण निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की बुनियाद और मज़बूत होगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ऐतिहासिक, दूरदर्शी व देश की बुनियाद को मज़बूत करने वाला बजट है। लोग भूले नहीं हैं कि कोविड-19 महामारी ने किस तरह से दुनिया पर प्रतिकूल असर डाला, जिसके कारण आज भी अनेक देश विभिन्न संकटों से जूझ रहे हैं। वहीं हमारे विशाल देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने अत्यंत कुशलतापूर्वक व बड़ी सूझबूझ से ऐसा संभाला, जिससे कि कोरोना महामारी के असर से देश कमोबेश उबर गया है।

यह हमारे देश की वास्तविक प्रगति ही मानी जाएगी कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। दुनिया के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के बीच भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा बजट पेश करना दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा संकेत है कि भारत विकास के पथ पर तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मोदी सरकार द्वारा पिछले लगभग साढ़े 8 साल में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के परिणामस्वरूप हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले दिनों में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस दिशा में भी केंद्र सरकार के इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से होने वाला है।

रक्षा, गृह, रेल, रोड, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, सहकारिता सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में इस बजट में समाहित किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बुनियादी सुविधाओं में इज़ाफा हो, गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की ताकत बढ़े, नौजवानों को रोज़गार मिले, टेक्नोलॉजी में हम आगे हो, इस दिशा में बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बजट से छोटे किसानों को काफी लाभ होगा, वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी के ज़रिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है ताकि किसानों को दीर्घकाल तक व्यापक लाभ मिलें। बजट में पशुपालकों, डेयरी व

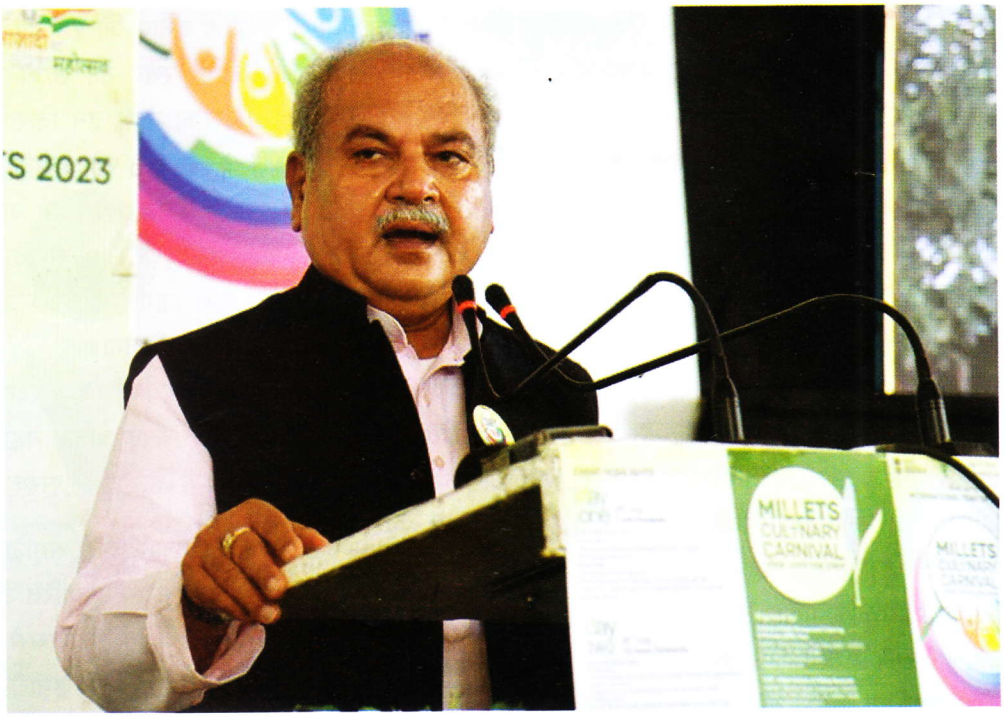

लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार हैं।
ई-मेल : agrimin.india@gmail.com

मत्स्यपालकों हेतु ऋण की निधि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि के साथ मील का पत्थर साबित होगा, जबकि वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय (डेयरी सहित) व मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का संयुक्त बजट सिर्फ 30223.88 करोड़ रुपये था।

सरकार द्वारा हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के ज़रिए विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्ष की राशि 70 करोड़ रुपये को बढ़ाकर अब 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए डिजिटल अवसंरचना को एग्रीटेक उद्योग एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्रदान करने तथा किसान केंद्रित समाधान के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63 हज़ार प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण शुरू किया जाना कोई साधारण बात नहीं है। हमारा सहकारिता क्षेत्र गाँव-गाँव में फैला हुआ है। सहकारिता कृषि पूरक है, जो परस्पर एक-दूसरे को मज़बूती प्रदान करेंगे।

प्राकृतिक खेती की पद्धति गौ-आधारित है। प्राकृतिक खेती बढ़ेगी तो गौवंश का भी पूरा-पूरा उपयोग होगा। पशुपालन किसानों की अतिरिक्त आमदनी का अहम स्रोत है, जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से सशक्त होगा। प्राकृतिक खेती को देश में जनांदोलन का स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है और इसे बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 459 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं उनकी सहायता करेगी, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 10 हज़ार बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

हमारे देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से काफी लाभ पहुँचाया गया है। हमारे इन छोटे किसान भाइयों-बहनों को केसीसी द्वारा इसी तरह सतत लाभ मिलता रहे, जिसके लिए इस बार 23 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना 6 हज़ार करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी, ताकि मछली पालक, मत्स्य विक्रेता, सूक्ष्म-लघु उद्योग अधिक सक्षम बनें। इससे मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार लाकर बाज़ार तक पहुँच बढ़ाई जाएगी।

छोटे-मझोले किसानों को कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के ज़रिए संगठित कर उन्हें खेती-किसानी से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है, जिसके लिए देशभर में 10 हज़ार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं। ये एफपीओ इन छोटे-मझोले किसानों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जिसका लाभ इन किसानों को मिलने लगा है। आगे भी यही गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए नए एफपीओ के गठन के संबंध में 955 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान इस साल किया गया है। एफपीओ के माध्यम से किसान संगठित रूप से खेती करेंगे तो उन्हें कम लागत में अच्छे आदानों के साथ अधिक उपज मिलेगी, दाम अच्छा मिलेगा।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है, जिसके लिए बजट बढ़ाकर 1623 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री किसान

'सहकार से समृद्धि' के मूलमंत्र के साथ सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इन सबका हमारी वृहद् अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के व्यापक विकास में भी सहायता मिलेगी।

देश को 'श्री अन्न' का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में की गई घोषणानुरूप मिलेट्स को 'श्री अन्न नाम से जाना जाएगा। 'श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों में भारत, विश्व में सबसे आगे है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष भारत की अगुवाई में मनाया जा रहा है।

सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 60 हज़ार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने के लक्ष्य के साथ युवा उद्यमियों के बीच कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापना की जाएगी, जिसके लिए अगले 5 साल हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भी एग्री स्टार्टअप्स को केंद्र द्वारा वित्तीय मदद दी जा रही है।

उद्यानिकी के लिए बजट राशि 1100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपये की गई है, वहीं आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड रुपये के प्रारंभिक खर्च से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त-गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।

चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइज़िंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज़ धन) नामक योजना

के तहत 10 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक व बॉयोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्र.श. का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष लाया जाएगा, जो ग्रामीण भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सतत लघु सिंचाई एवं पेयजल टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के अंतर्गत 5300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्टर फंड के माध्यम से गाँवों में बुनियादी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निरंतर बढ़ता कवरेज किसानों के लिए बहुत राहतदायी है। 'सहकार से समृद्धि' के मूलमंत्र के साथ सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इन सबका हमारी वृहद् अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के व्यापक विकास में भी सहायता मिलेगी।

कुल मिलाकर, भारतीय कृषि को और उन्नत व किसानों को समृद्ध बनाने के लिए किए जा रहे चौतरफा उपाय, **जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान-जय अनुसंधान** के मंत्र के साथ निश्चित रूप से देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर अमृतकाल तक सुनहरे पृष्ठों के साथ स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। ❑